फिल्म घूसखोर पंडत पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा–

समाज का बस अपमान करना जानती है भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर एकबार फिरतीखा हमला बोला है। सपा मुखिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा एक सोची–समझी साजिश के तहत विशिष्ट समाजों को लक्षित कर उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है। यह विवाद ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म/वेब सीरीज ''घूसखोर पंडत'' को लेकर है, जिसके शीर्षक और सामग्री पर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के आरोप लग रहे हैं।

माना जा रहा है कि यादव ने यह टिप्पणी ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' के संदर्भ में की है। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से फिल्म के नाम का जिक्र नहीं किया है।राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को फिल्म/वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' के निदेशक और उनकी टीम के खिलाफ़ एक जाति विशेष (ब्राह्मण) को अपमानित करने और वैमनस्यता फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। सपा अध्यक्ष यादव ने कहा कि वर्तमान में जिस फिल्म को लेकर मुद्दा बना है, उसके नाम का उल्लेख करना भी संभव नहीं है क्योंकि फ़िल्म का शीर्षक केवल आपत्तिजनक नहीं, बेहद अपनानजनक भी है। भाजपा कभी ये काम बयानबाज़ी से करती है और कभी बैठकों पर नोटिस देकर, कभी अपना पैसा लगाकर विज्ञापन, प्रचार सामग्री या फिल्म बनवाकर। और जब विवाद बढ़ जाता है तो गिरगिट की तरह रंग बदलकर घड़ियाली आंसू बहाती है और दिखावे के लिए सामने आकर झूठी कार्रवाई का नाटक करती है। सच तो ये है कि वो लक्षित किये हुए समाज विशेष को अपमानित–उत्पीड़ित देखकर मन–ही–मन बहुत खुश होती है। इस मौके पर पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव, शारदानंद अंचल,पूर्व विधायक अरुण वर्मा समेत समेत सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा हमेशा षड्यंत्र करती है

सपा प्रमुख ने कहा कि उस फिल्म का नाम लिखने से भाजपा का उस समाज का तिरस्कार करने का उद्देश्य और भी अधिक पूरा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स'पर एक पोस्ट में कहा, ' भाजपा हमेशा से ये षड्यंत्र करती है कि वो किसी समाज के कुछ लोगों का दुरुपयोग, उसी समाज के खिलाफ करती है। इससे वो किसी समाज विशेष को लक्षित, चिह्नित , टारगेट करके अपमानित-आरोपित' करती है।

भाजपा का एजेंडा चलाने वाले पैसे को छोड़कर किसी के सगे नहीं

यादव ने उक्त फिल्म को नाम बदलकर भी रिलीज नहीं करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,''जब निर्माताओं को आर्थिक हानि होगी, तभी ऐसी फिल्में बनना बंद होंगी क्योंकि पैसे के लालच में भाजपा का एजेंडा चलानेवाले भी भाजपाइयों की तरह पैसे को छोड़कर किसी और के सगे नहीं हैं। ये 'रचनात्मक स्वतंत्रता' या 'क्रि एटिव लिबर्टी' के हनन की बात नहीं है, ये 'रचनात्मक समझ' या कहिए 'क्रि एटिव प्रूडेंस' की बात है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित जो फिल्म किस एक पक्ष की भावनाओं को, एक सोची-समझी साज़िश के तहत आहत करे वो मनोरंजन कैसे हो सकती है।उन्होंने कहा, और अगर उद्देश्य मनोरंजन नहीं है तो किसी एक समाज को बदनाम करने के एजेंडे के पीछे के एजेंडे का खुलासा भी होना ही चाहिए।'

मेक इन इंडिया के शेर को लगता है जंग लग गई

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों और मेक इन इंडिया अभियान की सफलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यहां मेक इन इंडिया की सफलता पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने भारत का 500 अरब डॉलर का विशाल बाजार अमेरिका को सौंप दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का मेक इन इंडिया वाला शेर अब जंग खा चुका है। सपा प्रमुख ने सरकार के विरोधाभासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ हवाई अड्डों पर मिलेट्स (मोटा अनाज) के विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे विदेशों से आयात किया जा रहा है। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान का हवाला देते हुए कहा कि पशु आहार का आयात करना स्थानीय प्रयासों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन का काम मुख्य रूप से पिछड़े और दलित वर्ग के लोग करते हैं, जिनके हितों की अनदेखी कर सरकार विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बुनियादी मुद्दों पर बहस होती है, तो भाजपा सावरकर जैसे विषयों को बीच में ले आती है ताकि इतिहास के पन्नों में उलझाकर वर्तमान समस्याओं से ध्यान भटकाया जा सके।

मोदी सरकार ने बाहरी दबाव में आकर देश को बेच दिया

आप सांसद संजय सिंह ने कहा- भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से लाखों भारतीय किसान खतरे में पड़े

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एपस्टीन कांड में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बाहरी दबाव में आकर देश को बेच दिया और भारतीय किसानों के हितों के साथ विश्वासघात किया।

भारत और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने दावा किया कि इस समझौते ने भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया है, जिससे लाखों भारतीय किसान खतरे में पड़ गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के साथ घोर विश्वासघात किया है। संयुक्त बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी कृषि उत्पाद अमेरिकी बाजार के लिए खोल दिए गए हैं। जब अमेरिकी किसानों को हर साल लाखों की सब्सिडी मिलती है, तो भारतीय किसान कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? सिंह ने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने महंगे अमेरिकी तेल के पक्ष में रूस से तेल आयात कम कर दिया है, जिससे आम जनता पर 80,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अपने हमले को तेज करते हुए, आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि यह समझौता देश के साथ विश्वासघात है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम एपस्टीन फाइलों में आने के दबाव में देश को बेच दिया है। सिंह ने आगे कहा कि अमेरिका ने इतिहास में भारत के साथ विश्वासघात किया है, जबकि रूस मुश्किल समय में देश के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका से कोयला आयात करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और आरोप लगाया कि यह समझौता चुनिंदा व्यावसायिक हितों को लाभ पहुंचाता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हमें पता लगाना होगा कि इससे किन व्यापारियों को फायदा हो रहा है। एक पोस्ट में, सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश से झूठ बोलने और अमेरिकी कृषि उत्पादों को शुल्क–मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया था, और चेतावनी दी थी कि सस्ते आयात से घरेलू बाजार तबाह हो जाएंगे। इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए,आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अतीत में राजनीतिक रूप से कमजोर सरकारों ने भी भारत के हितों को अमेरिका के सामने समर्पित नहीं किया था। वाशिंगटन पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा भारत को उसी तरह चलाने का है जिस तरह वे वेनेजुएला को चला रहे हैं।

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी भाजपा से जुड़े हैं : अशोक गहलोत

» बोले पूर्व सीएम- चार साल बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर एकबार फिर तीखा प्रहारकिया है। गहलोत नेआरोप लगाया कि वर्ष 2022 में हुई इस नृशंस हत्या के आरोपी भाजपा से जुड़े हुए थे, और इसी कारण मामले के सीधा और स्पष्ट होने के बावजूद चार साल बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर त्वरित कार्रवाई की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी। उन्होंने कहा, 2022 से 2026 तक कन्हैयालाल का परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले की स्थिति और आरोपियों को सजा दिलाने के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सजा में हो रही देरी को लेकर जनता में आशंका बढ़ रही है और इसका कारण आरोपियों का भाजपा से जुड़ा होना बताया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि चुनावों के दौरान इस मुद्दे का राजनीतिकरण झूठे दावों के साथ किया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी गई है। गहलोत ने कहा, देश यह सब देख रहा है और समय आने पर जवाबदेही तय होगी।

बामुलाहिजा
कार्टून: हसन जैदी

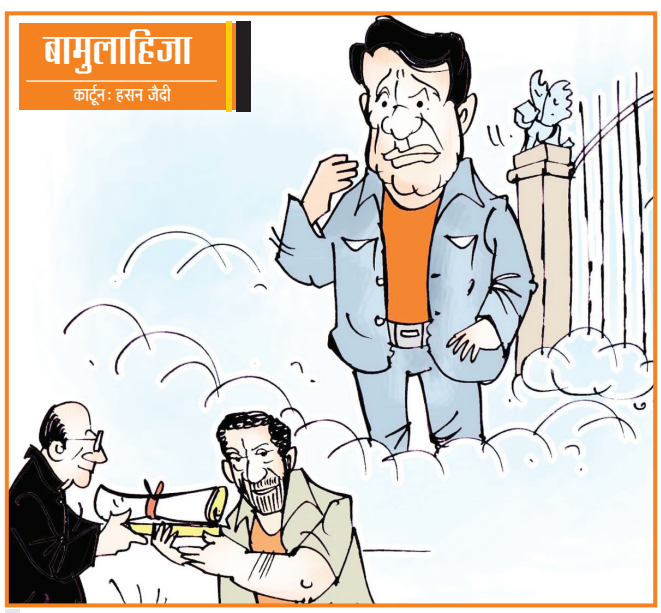

रेल मंत्रालय राज्य में स्वीकृत रेलवे की धनराशि शीघ्र जारी करे: स्टालिन

» तमिलनाडु के सीएम ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लिखा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय को राज्य में स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने और लंबित परियोजनाओं को पुन: शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

स्टालिन ने पत्र में कहा, ''रेल मंत्रालय से धनराशि जारी करने में हो रही देरी'' और विभिन्न परियोजनाओं के लिए टुकड़ों में निधि आवंटित किए जाने की व्यवस्था के कारण कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार,

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए 2,500.61 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, लेकिन रेलवे विभाग ने अब तक 931.52 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि आवंटित नहीं की है। स्टालिन ने कहा, ''निधि जारी करने में देरी और टुकड़ों में आवंटन ने तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डाली है। इससे प्रभावित भूमि मालिकों के लिए लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।'' उन्होंने बताया कि 19 प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 94 प्रतिशत पूरा हो चुका है और 1,198.02 हेक्टेयर भूमि रेलवे को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 'तिरुवनंतपुरम–कन्याकुमारी दोहरीकरण' परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मुआवजे के लिए आवश्यक 289.78 करोड़ रुपये जारी न किए जाने के कारण 16.86 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अब भी रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ''संपूर्ण धनराशि और इसे प्राथमिकता के आधार पर'' जारी किया जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रि या सुचारू रूप से पूरी की जा सके।